Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to provide funds for various drinking water projects in Barmer Parliamentary Constituency, Rajasthan.

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर)ः जैसलमेर-बाडमेर, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, का भौगालिक क्षेत्रफल 60,000 वर्ग किमी. एवं जनसंख्या 33 लाख है। मेरे लोक सभा क्षेत्र का कुल 743 किमी. का क्षेत्र पश्चिम में भारत-पाक सीमा से सटा है। यहाँ आर्मी, एयरफोर्स एवं बी.एस.एफ. के सैनिक भी तैनात हैं। थार मरूस्थल होने के नाते यदि गत 60 साल का रिकार्ड देखा जाए, तो 40 साल अकाल पड़ा है। इस साल भी 17 तहसीलों में से 10 तहसीलों में बरसात की एक बूंद भी नहीं पड़ी है और यह क्षेत्र 85 प्रतिशत डार्क जोन है तथा शेष क्षेत्र में पानी जमीन में 400 से 1000 फीट नीचे है। साथ ही, जो पानी है वे 2000-3000 टीडीएस है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार पानी पीने योग्य ही नहीं है। इस पानी के पीने से लोगों को बीमारियाँ लग गई हैं। इस प्रकार से, इस क्षेत्र में पेयजल की भयंकर समस्या है। ऐसी स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार एवं राज्य सराकर के प्रयासों से 1995 में प्रारम्भ इन्दिरा गांधी नहर जैसलमेंर में सीमावर्ती क्षेत्र तक पहुँची एवं नर्मदा नहर बाडमेर पहुंची। इस पर आधारित बड़ी पेयजल योजनाएं बनाई गई हैं। नर्मदा नहर परियोजनाओं को चालू करने में हमारे प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब बड़ा सहयोग मिला। जिसके लिए मैं उन्हें क्षेत्रीय जनता की ओर से धन्यवाद देता हूँ। दोनों नहरों पर 2003 से 2008 तक भाजपा सरकार द्वारा योजनाएं बनाइ गई थी। परंतु 2008 से 2013 तक की अवधि में इस ओर ध्यान नहीं देने के कारण योजनाओं को गति नहीं मिल पाई तथा तत्कालीन सरकार ने 4 साल तक इन योजनाओं में बजट नहीं दिया।

बाडमेर-जैसलमेर जिले की जनता को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु इन्दिरा गांधी नहर पर आधारित-(1) राजीव गांधी लिफ्ट नहर (उम्मेदसागर-धवा-समदडी-खण्डप) राशि 585.40 करोड़ रूपए, (2) आर.डी. नाचना (पोखरण-फलसुण्ड-सिवाना)रशि 1454.20 करोड़ रूपए (3) आर.डी. मोहनगढ़ (बाडमेर लिफ्ट परियोजना का प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ चरण) राशि 1716.01 करोड़ रूपए, नर्मदा नहार आधारित (4) चोहटन एवं गुडमालानी योजना-राशि 1467.08 करोड़ रूपए (5) एच.आर. गुडमालानी योजना- राशि 160.00 करोड़ रूपए (6) रामसर-शिव एवं चौहटन- 160.7 करोड़ रूपए कुल- राशि 5993.00 करोड़ रूपए। यदि इन नई छह योजनाओं में अगामी 3-4 साल में माँग के अनुसार पूरी राशि दी जाए, तो क्षेत्र की 85 प्रतिशत जनता पाईप लाइन के माध्यम से पेयजल से लाभान्वित हो जाएगी जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की घोषणा और मोदी जी के सपनों को साकार करने की ओर एक अहम कदम होगा। इस संबंध में हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी दिनांक 11.08.2015 को माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एंव पेयजल मंत्री श्री बिरेंद्र सिंह जी को एक डी.ओ. लेटर लिखकर 34000 करोड़ रू. की राशि की माँग की है। जिनमें से 6000 करोड़ रू. मेरे क्षेत्र से ही संबंधित है। इस संबंध में मैंने पूर्व में दिनांक 10.05.2015 को नियम 193 के तहत चर्चा में एवं 16.12.2015 को नियम 377 के तहत संसद की कार्यवाही में सरकार का ध्यान आकर्षित भी किया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं जल संसाधन मंत्री जी से विशेष निवेदन करता हूँ कि जो उक्त योजनाएं बजट के अभाव में बंद हैं उन छह योजनाओं के लिए 6000 करोड़ रू. के बजट का इंतजाम केन्द्र सरकार के NRDWP या अन्य Centrally Funded Scheme से

करायें या राज्य सरकार को World Bank को राशि उपलब्ध करवाने में सहयोग प्रदान कर इस क्षेत्र हेतु विशेष पैकेज जारी करावें, ताकि सदियों से अभावग्रस्त जनता को राहत मिल सके।